[2008] 1 S.C.R. 795

उषा देवी

बनाम

विजवान अहमद एवं अन्य

(सी.ए. 2008 की संख्या 481)

17 जनवरी 2008

(जी.पी. माथुर और आफताब आलम, जज)

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश 6 नियम 17:

याचिका में संशोधन - प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए याचिका - प्लेन्ट की अनुसूची में संपत्ति का विवरण सही करने के लिए संशोधन याचिका - निचली अदालत द्वारा अस्वीकृत - उच्च न्यायालय द्वारा चुनौती खारिज - अपील पर, निर्णय: सूट की संपत्ति का गलत विवरण प्रतिवादियों द्वारा केवल लिखित बयान में ही नहीं, बल्कि एक विविध मामले की प्रक्रिया के दौरान भी स्पष्ट रूप से उठाया गया था। याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा यथार्थ मुद्दों के निपटारे के बावजूद प्लेन्ट में असंगतता को उठाने में उचित सावधानी की कमी थी। आदेश 6 नियम 17 की उप-धारा के अनुसार, ट्रायल की शुरुआत के बाद संशोधन प्रतिबंधित है, जब तक कोर्ट इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि पक्ष ने ट्रायल की शुरुआत से पहले उचित सावधानी के बावजूद मामले को नहीं उठाया। यद्यपि ट्रायल की शुरुआत के समय को लेकर कोई निर्णायक बयान देने से परहेज करते हुए, कोर्ट ने निर्णय दिया कि संशोधन आवश्यक था ताकि पक्षों के बीच विवाद का असली प्रश्न सामने आ सके और यदि याचिकाकर्ता सूट में सफल होता है, तो निष्पादन के चरण में जटिलताएँ उत्पन्न न हों। अत:, संशोधन की अनुमति दी गई। यदि चाहा जाए, तो प्रतिवादी अपने लिखित बयान में संबंधित संशोधन कर सकता है।

अपीलकर्ता ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रतिवादियों-आरोपियों के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें उन्हें सूट संपत्ति पर उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करने से रोका गया और उन्हें सूट भूमि पर पहले से मौजूद भवन को बनाने या तोड़ने से निर्देशित किया गया। सूट परिसर का विवरण प्लेन्ट की अनुसूची में दिया गया था। प्रतिवादी-आरोपियों ने अनुसूची में दिए गए सूट संपत्ति के विवरण पर आपत्ति उठाई। बाद में, अपीलकर्ता-प्लेनटीफ ने आदेश 39, नियम 2(A) और धारा 151 सी.पी.सी. के तहत एक विविध याचिका दायर की। उस प्रक्रिया में, प्लेनटीफ के पति को एक गवाह के रूप में परीक्षा में लाया गया और उन्होंने दावे पर कायम रहते हुए कहा कि विवादित संपत्ति को प्लेन्ट में सही तरीके से वर्णित किया गया था। हालांकि, बाद में, प्लेनटीफ ने संशोधन याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि अनजाने में सूट भूमि का विवरण प्लेन्ट की अनुसूची में गलत था। याचिका को निचली अदालत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि अदालत ने माना कि प्लेनटीफ ने उचित सावधानी के बावजूद लगभग 2 साल के मुद्दों के निपटारे के बाद इस असंगतता को प्लेन्ट में नहीं उठाया और गवाहों को एक विविध मामले में शपथ

पर परीक्षा दी गई। निचली अदालत के आदेश से आहत होकर, प्लेनटीफ ने एक रिट याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतः वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता ने तर्क किया कि नियम की उप-धारा तब ही लागू होती है जब ट्रायल शुरू हो चुका हो और इस मामले में निचली अदालत ने उप-धारा में उचित सावधानी क्लॉज को लागू करने में गलती की; कि न तो मुद्दों की गठन को और न ही विविध मामले की प्रक्रिया को ट्रायल की शुरुआत के रूप में लिया जा सकता है; कि संशोधन के लिए याचिका प्री-ट्रायल चरण में दायर की गई थी और इसलिए, याचिका को अनसंशोधित नियम 17 के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए थी।

प्रतिवादियों ने यह तर्क किया कि याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ संपत्ति के संबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की थी जैसा कि प्लेन्ट में वर्णित है और प्रस्तावित संशोधन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादियों को अपनी ही संपत्ति के संबंध में लंबे समय तक निषेधाज्ञा का सामना करना पड़ा; कि याचिकाकर्ता की अपनी स्थिति के अनुसार सूट वर्तमान रूप में विफल होने के लिए बाध्य था और प्लेन्ट में संशोधन की अनुमति देना उसे अनुचित लाभ देने के बराबर होगा; कि प्रस्तावित संशोधन न केवल सूट संपत्ति को बदल देगा बल्कि यह कारण भी बदल देगा और इस प्रकार सूट को किसी भी स्थिति में बनाए रखना असंभव हो जाएगा; और यह कि संशोधन के लिए याचिका ट्रायल की शुरुआत के बाद की गई थी।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने यह निर्णय दिया:

1.1 संशोधित रूप में, नागरिक प्रक्रिया संहिता का आदेश 6 नियम 17 एक उप-धारा शामिल करता है जो ट्रायल की शुरुआत के बाद किसी भी संशोधन को बार करती है, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि उचित सावधानी के बावजूद पक्ष ने ट्रायल की शुरुआत से पहले मामले को नहीं उठाया। (पैरा - 5) [801-F]

1.2 निचली अदालत ने पाया और निर्णय दिया कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित सावधानी की पूर्ण कमी थी, क्योंकि सूट संपत्ति का गलत विवरण प्रतिवादियों द्वारा केवल लिखित बयान में ही नहीं, बल्कि विविध मामले की प्रक्रिया के दौरान भी स्पष्ट रूप से उठाया गया था। (पैरा 6) [801-G]

2.1 इस कोर्ट के सज्जन कुमार मामले के निर्णय के मद्देनजर, इस अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए। (पैरा 10) [805-C]

2.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कोर्ट का आदेश किसी भी बड़े मुद्दे पर निर्णय देने का प्रयास नहीं करता है कि सूट की ट्रायल की शुरुआत का चरण कौन सा होगा, लेकिन इस कोर्ट ने पाया कि वर्तमान अपील सज्जन कुमार के निर्णय के तथ्यों के करीब है और उस निर्णय का पालन करते हुए वर्तमान अपील में संशोधन की याचिका भी स्वीकार की जानी चाहिए। (पैरा-10) [805-D]

सज्जन कुमार बनाम राम किशन (2005) 13 SCC 89 पर भरोसा किया गया।

अर्जेंद्रप्रसादजी एन. पांडेय एवं अन्य बनाम स्वामी केशवप्रकाशदासजी एन. एवं अन्य (2006) 12 SCC 1 - लागू नहीं किया गया।

उषा देवी बनाम रिजवान अहमद और अन्य

2.3 प्रतिवादियों-प्रतिवादकों को अपने लिखित बयान में कोई संबंधित संशोधन करके संशोधित प्लेन्ट पर अपनी आपत्ति उठाने का अधिकार होगा। (पैरा - 11) [805-F]

2.4 प्रतिवादियों के इस तर्क के बारे में कि प्लेन्ट में सूट संपत्ति के विवरण के परिणामस्वरूप प्रतिवादियों को अपनी संपत्ति के खिलाफ निषेधाज्ञा का सामना करना पड़ा, न्याय की पूर्ति प्रस्तावित संशोधन को अनुमति देकर की जाएगी, इसके साथ 10,000 रुपये की लागत। (पैरा-12) [805-G & H]

2.5 अपीलकर्ता को प्रस्तावित संशोधन को प्लेन्ट में करने की अनुमति दी जाती है, प्रतिवादियों-प्रतिवादकों को 10,000 रुपये की लागत के भुगतान के साथ। (पैरा 12) [806-A]

सिविल अपीलीय न्यायाधिकार: सिविल अपील नंबर 481 ऑफ 2008

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 13.7.2006 को जारी अंतिम आदेश और निर्णय से

देवाशिष भारुका, हंसा भारुका, अभिषेक मोहन सिन्हा और डॉ. सुशील बलवाड़ा ने अपीलकर्ता के लिए प्रस्तुत किया।

एस.आर. शर्मा और एस. बालाजी ने प्रतिवादियों के लिए प्रस्तुत किया।

अदालत का निर्णय

आफताब आलम, जज द्वारा सुनाया गया। 1 अनुमति दी गई।

2 यह अपील 13 जुलाई 2006 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ है, जो कि W.P. (C) संख्या 2325 ऑफ 2006 में दिया गया था। यह एक संक्षिप्त और अस्पष्ट आदेश है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को पुष्टि दी, जिसने याचिकाकर्ता की याचिका को आदेश 6, नियम 17 के तहत खारिज कर दिया था जिसमें सूट संपत्ति का संशोधन किया जाना था जैसा कि प्लेन्ट के अनुसूची में वर्णित था।

3 मामले की प्रमुख तथ्य संक्षिप्त और सरल हैं। वर्ष 2002 में, याचिकाकर्ता ने एक सूट दायर किया, जिसमें प्रतिवादियों-प्रतिवादकों को सूट संपत्ति पर उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करने से रोकने और उन्हें सूट भूमि पर पहले से मौजूद भवन को बनाने या ध्वस्त करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। प्लेन्ट के अनुसूची में सूट स्थल का विवरण इस प्रकार दिया गया था:

"दक्षिणी आधा भाग जिसका क्षेत्रफल 1937.97 वर्ग फीट 0.04.448 एकड़ या 0.04.9/20 एकड़ है, वर्तमान में होल्डिंग नंबर 304, पहले 275 और वर्तमान में 201, वार्ड नंबर IV (पुराना) नया 13, गिरिडीह नगरपालिका में स्थित है, जिसमें एक दो मंजिला घर है और यह भूमि निम्नलिखित सीमा में है: -

XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX"

प्रतिवादी-प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में सूट संपत्ति के वर्णन पर विशेष आपत्ति उठाई। प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि भूमि का क्षेत्रफल जो विवाद का विषय हो सकता है, बहुत छोटा था और याचिकाकर्ता ने उन संपत्तियों का वर्णन किया था जो कानूनी रूप से उनकी थीं। याचिकाकर्ता की ओर से लिखित बयान पर कोई पुनः उत्तर नहीं दिया गया और मुद्दों को 13 अगस्त 2002 को तैयार किया गया। इसके बाद, सूट की प्रक्रिया स्थगित रही, लेकिन 5 अगस्त 2002 को याचिकाकर्ता ने आदेश 39, नियम 2(A) और धारा 151 सी.पी.सी. के तहत एक विविध याचिका (जिसे विविध मामला संख्या 28/2002 के रूप में पंजीकृत किया गया) दायर की, जिसमें उनके पक्ष में पहले दी गई अंतरिम निषेधाज्ञा का कथित उल्लंघन था। उस प्रक्रिया में, याचिकाकर्ता के पति को एक गवाह के रूप में परीक्षण के दौरान पेश किया गया। क्रॉस-एक्जामिनेशन के दौरान, उन्हें बार-बार यह बताया गया कि उन्हें सूट भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वे प्लेन्ट में उल्लिखित सभी क्षेत्र का दावा नहीं करेंगे बल्कि याचिकाकर्ता का दावा केवल एक दशक भूमि पर होगा। उन्हें यह भी सुझावित किया गया कि शेष भूमि स्वीकृत रूप से प्रतिवादियों की है और पार्टियों के बीच किसी भी विवाद का विषय केवल एक बहुत सीमित क्षेत्र हो सकता है, पूरी संपत्ति नहीं जैसा कि प्लेन्ट में वर्णित है। गवाह (याचिकाकर्ता का पति) ने प्रतिवादियों की ओर से किए गए सुझावों को खारिज कर दिया और यह दावा किया कि विवादित संपत्ति सही रूप से प्लेन्ट में वर्णित थी और यही सूट का विषय था। बाद में, 29 सितंबर 2004 को संशोधन याचिका दायर की गई जिसने वर्तमान अपील को जन्म दिया। संशोधन याचिका में कहा गया कि लापरवाही के कारण सूट भूमि को प्लेन्ट के अनुसूची में गलत तरीके से वर्णित किया गया था और यह गलती सुधारने की आवश्यकता थी। यह भी कहा गया कि वास्तव में, एक दशक, जो मानक माप द्वारा 9 छटाक के बराबर है, यानी, 414 वर्ग फीट की भूमि (कुछ संरचना के साथ) सूट का विषय था। तदनुसार, यह प्रार्थना की गई कि सूट संपत्ति के विवरण से प्रारंभिक शब्द "दक्षिणी आधा भाग जिसका क्षेत्रफल 1937.97 वर्ग फीट = 0.04.448 एकड़ या 0.04.9/20 एकड़ है" को हटा दिया जाए और निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए:

> "1 दशक (एक दशक) जो मानक माप द्वारा लगभग 9 छटाक (नौ छटाक) है, यानी 414 वर्ग फीट भूमि के साथ पुराने दो मंजिला घर जिसमें चार कमरे हैं, दो कमरे ग्राउंड फ्लोर में और दो कमरे पहले मंजिल में और एक वेरांडा पश्चिम की ओर जो सड़क के किनारे कवर किया गया है, एक सीढ़ी जो ऊपरी मंजिल के कमरों तक जाती है।" वर्तमान में होल्डिंग नंबर 304 पर स्थित है।.....

4 निचली अदालत ने 2 फरवरी 2006 को याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

> "इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने 29.09.04 से पहले, यानी मुद्दों के समाधान के लगभग 2 साल बाद और विविध मामले 28/2002 के तहत गवाहों की शपथ के बाद, सूट में इस भिन्नता को नहीं उठाया।
>
> "इसलिए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को सूट की अनुसूची में भिन्नता को ठीक करने के लिए पर्याप्त अवसर होने के बावजूद, उन्होंने इसे ठीक करने की परवाह नहीं की, बल्कि भूमि और सीमा की सहीता को बार-बार दावा किया।"

उषा देवी बनाम रिजवान अहमद और अन्य

निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि विवादित आदेश में कोई अवैधता नहीं थी।

5 प्लीडिंग्स का संशोधन पहले न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान एक आसान प्रक्रिया थी, जब तक कि सी.पी.सी. में 1999 में संशोधन नहीं किए गए। यह महसूस किया गया कि प्लीडिंग्स के संशोधन के प्रावधान (आदेश 6, नियम 17) का अत्यधिक दुरुपयोग किया गया और यह न्यायिक प्रक्रिया में देरी का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसके अनुसार, विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार, प्लीडिंग्स के संशोधन का प्रावधान अधिनियम 46/1999 द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया। इस प्रावधान की समाप्ति ने वकीलों और विभिन्न कानूनी संगठनों द्वारा व्यापक विरोध उत्पन्न किया और इसके परिणामस्वरूप, अधिनियम 22/2002 द्वारा, 1 जुलाई 2002 से प्रभावी होते हुए, प्रावधान को फिर से पेश किया गया, हालांकि एक शर्त के साथ। इसके संशोधित रूप में, नियम 17, आदेश VI में एक प्रावधान शामिल है जो मुकदमे की शुरुआत के बाद किसी भी संशोधन को रोकता है, जब तक कि अदालत यह निष्कर्ष पर न पहुंचे कि उचित परिश्रम के बावजूद पार्टी ने मुकदमे की शुरुआत से पहले मामला नहीं उठाया।

6 जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, निचली अदालत ने पाया और यह घोषित किया कि याचिकाकर्ता-याचिकाकर्ता की ओर से उचित परिश्रम की कमी थी, क्योंकि सूट संपत्ति का गलत वर्णन प्रतिवादियों द्वारा केवल लिखित बयान में नहीं बल्कि विविध मामले की प्रक्रिया के दौरान भी स्पष्ट रूप से उठाया गया था।

7 श्री देवाशिश भारूका, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता, ने प्रस्तुत किया कि नियम के प्रावधान तब लागू होंगे जब मुकदमे की शुरुआत हो चुकी हो और इस मामले में निचली अदालत ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को खारिज करने में गलती की, जिसमें प्रावधान में उचित परिश्रम की धाराओं का हवाला दिया गया। अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि न तो मुद्दों की तैयारी और न ही विविध मामले की प्रक्रिया को मुकदमे की शुरुआत के रूप में लिया जा सकता है। संशोधन के लिए प्रार्थना पूर्व-मुकदमे के चरण में की गई थी और इसलिए, प्रार्थना को बिना किसी कठिनाई के अनुमति दी जानी चाहिए थी जैसा कि संशोधित नियम 17 के तहत था।

8 श्री एस.आर. शर्मा, प्रतिवादी-प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता, ने दूसरी ओर प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ सूट संपत्ति के संबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की थी और अब प्रस्तावित संशोधन से यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिवादियों को अपनी संपत्ति के संबंध में लंबे समय तक निषेधाज्ञा का सामना करना पड़ा। उनके अनुसार, संशोधन की प्रार्थना को केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए और प्रार्थना को अनुमति देना काफी असंगत, अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के अपने दिखाए गए प्रमाणों के अनुसार, सूट मौजूदा रूप में विफल होने वाला था और इसलिए, प्लेन्ट में संशोधन की अनुमति देना याचिकाकर्ता को अनुचित लाभ देने के बराबर होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित संशोधन केवल सूट संपत्ति को ही नहीं बदलेगा बल्कि कारण कार्रवाई को भी बदलेगा और इस प्रकार सूट को किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं बनाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि संशोधन की प्रार्थना मुकदमे की शुरुआत के बाद की गई थी और इसलिए निचली अदालत ने सही तरीके से प्रार्थना को खारिज कर दिया। उन्होंने इस आधार पर समर्थन किया कि मुद्दों की तैयारी मुकदमे की शुरुआत का संकेत देती है। इस संबंध में, *श्री शर्मा ने अजेंद्रप्रसादजी एन. पांडेय एवं अन्य बनाम स्वामी केशवप्रकाशदासजी एन. एवं अन्य* [2006 (12) SCC 1] में इस कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया। निर्णय के पैरा 57 में निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

"यह प्रस्तुत किया गया है कि मुद्दों की तैयारी की तिथि मुकदमे की शुरुआत की तिथि है। (कैलाश बनाम नन्हकू [2005 4 SCC 480]) मुद्दों की तैयारी की तिथि को मुकदमे की शुरुआत की तिथि मानने या शपथ पत्र की तारीख को जो परीक्षा-में-प्रमुख के रूप में माना जाता है, मुकदमे की शुरुआत की तिथि मानने से मामला आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के प्रावधान के अंतर्गत आता है। प्रतिवादी को, इसलिए, यह साबित करना होगा कि उचित परिश्रम के बावजूद, वह मुकदमे की शुरुआत से पहले मामला नहीं उठा सका। हमने पहले ही प्रतिवादी 1 और 2 (याचिकाकर्ता) की ओर से उचित परिश्रम की कमी को साबित करने वाले तारीखों और घटनाओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है।"

उपरोक्त उद्धृत अंश से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय ने यह नहीं माना कि मुद्दों की निपटान से मुकदमे की शुरुआत होती है। निर्णय के पहले के भाग में, अदालत ने तारीख दर तारीख की कार्यवाही की गहराई से जांच की और इस आधार पर पाया कि संशोधन के लिए प्रार्थना मुकदमे की शुरुआत के बाद की गई थी।

9 श्री भारूका ने दूसरी ओर, इस कोर्ट के एक अन्य निर्णय में ध्यान आकर्षित किया, जो कि बलदेव सिंह और अन्य बनाम मनोहर सिंह और अन्य [2006 (6) SCC 498] का है। निर्णय के पैरा 17 में निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

"हम इस आदेश के साथ विदा लेते समय यह भी नोट करना चाहेंगे कि आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के प्रावधान के अनुसार, सूट की सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है, तो प्लीडिंग्स के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कारण से, हमने रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि, वास्तव में, जाँच अब तक शुरू नहीं हुआ है। रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि पक्षों ने अभी तक सूट में अपने दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए हैं। रिकॉर्ड से यह भी प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा पाया गया कि सूट समाप्ति के कगार पर नहीं था। इसके अतिरिक्त, आदेश 6 नियम 17 में उपयोग किए गए मुकदमे की शुरुआत को सीमित अर्थ में समझा जाना चाहिए जैसे कि सूट की अंतिम सुनवाई, गवाहों की परीक्षा, दस्तावेजों की फाइलिंग और तर्कों की पेशकश। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, पक्षों ने अभी तक अपने दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, हम प्लीडिंग्स में संशोधन की याचिका को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जो आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के प्रावधान के अनुसार कोर्ट को किसी भी प्रक्रिया के चरण में प्लीडिंग्स के संशोधन की अनुमति देने की व्यापक शक्ति और बिना किसी बाधा के विवेक प्रदान करता है।"

श्री भारूका ने इस कोर्ट के एक अन्य निर्णय की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जो कि *सज्जन कुमार बनाम राम किशन* [2005 (13) SCC 89] का है। इस निर्णय में भी प्रस्तावित संशोधन सूट संपत्तियों के वर्णन को सही करने से संबंधित था। संशोधन की याचिका दी गई थी कि किरायेदारी नोट में दिए गए संपत्ति का वर्णन गलत था और वही वर्णन प्लेनेट में दोहराया गया था और निष्पादन के चरण पर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती थीं, जिसे बचाने के लिए सूट संपत्तियों के वर्णन को सही करने की आवश्यकता थी। मामले में एक अन्य समानता यह थी कि संशोधन की प्रार्थना का विरोध प्रतिवादी-प्रतिवादियों द्वारा इस प्रधान आधार पर किया गया कि हालांकि प्रतिवादी ने लिखित बयान में ही यह दावा किया था कि सूट संपत्तियों का वर्णन सही नहीं था, फिर भी याचिकाकर्ता ने सूट की सुनवाई जारी रखी और प्रारंभिक चरण में संशोधन की याचिका नहीं की। निचली अदालत ने संशोधन की प्रार्थना

को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सिविल रिवीजन को खारिज कर दिया। इस कोर्ट ने संशोधन की प्रार्थना को अनुमति दी और निर्णय के पैरा 5 में निम्नलिखित अवलोकन किया:

> "पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद, हम संतुष्ट हैं कि अपील को अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि निचली अदालत ने संशोधन की प्रार्थना को खारिज करते हुए उस कानून के अंतर्गत उसे दी गई न्यायिक अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया और इस अधिकारिता का प्रयोग न करके न्याय की संभावित विफलता को जन्म दिया। निचली अदालत द्वारा की गई ऐसी गलती को उच्च न्यायालय ने अपनी निगरानी अधिकारिता के तहत सही किया जाना था, भले ही धारा 115 सी.पी.सी. सख्ती से लागू नहीं होती। *यह सच है कि याचिकाकर्ता को सूट के प्रारंभिक चरण में प्लेनेट में संशोधन के लिए सावधान रहना चाहिए था, विशेष रूप से जब प्रतिवादी ने लिखित बयान में ही याचिकाकर्ता की गलती को उजागर किया था। फिर भी, हम मानते हैं कि प्रस्तावित संशोधन पक्षों के बीच वास्तविक विवाद के प्रश्न को उजागर करने के उद्देश्य से आवश्यक था और संशोधन की अनुमति देने से इनकार करने से यदि याचिकाकर्ता सूट में सफल होता है, तो निष्पादन के चरण पर अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी।*"

10 *सज्जन कुमार* के निर्णय को देखते हुए, हम मानते हैं कि इस अपील को भी अनुमति दी जानी चाहिए। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस आदेश में हम मुकदमे की प्रक्रिया की शुरुआत के चरण पर कोई व्यापक निर्णय नहीं देते, बल्कि हम केवल यह मानते हैं कि इस अपील के तथ्य *सज्जन कुमार* के निर्णय से मेल खाते हैं और उस निर्णय का अनुसरण करते हुए इस अपील में संशोधन की प्रार्थना को अनुमति दी जानी चाहिए।

11 प्रतिवादियों की ओर से की गई इस आपत्ति के बारे में कि संशोधन से मुकदमा अमान्य हो जाएगा क्योंकि यह केवल मुकदमे की संपत्ति को ही नहीं बल्कि कारण को भी बदल देगा, केवल यह कहा जा सकता है कि संशोधन की प्रार्थना को अनुमति देने के लिए संशोधन की मेरिट कोई महत्वपूर्ण विचार नहीं है और प्रतिवादी-उत्तरदाता अपने लिखित उत्तर में किसी भी अनुरूप संशोधन करके संशोधित याचिका पर आपत्ति उठा सकते हैं।

12 प्रतिवादियों के वकील ने यह भी कहा कि याचिका में संपत्ति का विवरण देने के कारण प्रतिवादी-उत्तरदाता को अपनी खुद की संपत्ति के खिलाफ स्थगन का सामना करना पड़ा। हमें लगता है कि प्रस्तावित संशोधन की अनुमति देने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होगी, बशर्ते प्रतिवादियों को 10,000 रुपये की लागत का भुगतान किया जाए।

13 इस अपील को अनुमोदित किया जाता है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को याचिका में प्रस्तावित संशोधन करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं को 10,000 रुपये की लागत का भुगतान किया जाए। संशोधन तब अनुमोदित किया जाएगा जब लागत की राशि आज के दो महीने के भीतर भुगतान की जाती है।

एस.के.एस. अपील अनुमोदित की गई।

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**